कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सम्मानित उपसभापति महोदय, मलेशिया में रह रहे भारतीयों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार का जिक्र यहां सदन में हुआ है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। इस संबंध में, भारत सरकार की ओर से, इस मैटर को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए मलेशियन गवर्नमेंट के साथ टेक-अप किया जा रहा है। चूंकि यह मामला अत्यंत गंभीर है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उन्हें यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या हुआ है, इसकी जानकारी संबंधित मंत्री सदन को दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Legislative Business, the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Bill, 2007. Shri Murli Deora to move the Motion.

GOVERNMENT BILL

The Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Bill, 2007

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): Sir, I move:

> "That the Bill to declare the institution known as the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, be taken into consideration"

Sir, the Government introduced the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Bill, 2007 in the Rajya Sabha on 7th September, 2007.

I would like to apprise the hon'ble Members about the need of setting up of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology and its declaration as the "Institute of National Importance". The year 1999 witnessed the advent of the New Exploration Licensing Policy, which has been progressively made more and more attractive. This policy has evoked great enthusiasm among foreign companies as well as Indian private and public sector companies for acquiring exploration acreages in India. As on date, only 30% of the sedimentary basins in India has been explored. It is planned to increase the exploration coverage to an extent of 100% by the year 2015. In this context, apart from technology, availability of adequate number of qualified personnel would be a prime requirement in the coming years.

Sir, in a recent study conducted by consultant Pricewaterhouse Coopers for Petrofed, it is estimated that the gap between the availability and requirement of trained manpower in the field of Petroleum Technology in India would be about 3600 by the year 2019. To substantially meet the shortfall of trained manpower in the petroleum sector, it has been decided by the Government to set up Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (RGIPT) at Jais, UP.

The institute is designed to serve as the fountainhead for the nurturing of world class technical human resources capable of serving as the leaders and innovators of tommorow in the field of Petroleum Technology. To start with, the Institute will commence its academic operations by admitting students in basic undergraduate courses from the academic year 2008-09, from a rented campus. On its becoming fully operational the Institute world have 7 B.Tech, 6 Integrated Masters Degrees, 8 M. Tech/MBA and 12 PGD and Ph. D. programmes.

The total estimated capital cost of the project is Rs. 435 crores which would be met partially through budgetary support of Rs. 285 crores and Rs. 150 crores from Oil Industry Development Board. The total estimated recurring expenditure of Rs. 260.58 crores would be met from the accrual of interest on Endowment Fund of Rs. 250.00 crores to be created

with the contribution of Oil Public Sector Undertakings (PSUs), student fees, donations and others earnings of the Institute. The Institute is envisaged to be self-sufficient by the year 2015-16. It is proposed that RGIPT would have a high degree of autonomy in terms of its academic, administrative and financial functioning. RGIPT would have legal empowerment in its own right to enable it to grant degrees and other academic distinctions and titles. Furthermore, it is envisaged that RGIPT would enjoy the patronage and support of the Ministry of Petroleum & Natural Gas of Government of India. It is in the interest of the nation that the Government nurture the institute in its nascent and crucial stage of development to enable the Institute to launch and run its programmes without compromise and set up world-class infrastructure while offering courses of a high standard, in the absence of the status of the "institute of National importance", it would not be possible to attract eminent faculty members and meritorious students.

In view of the proposed mode of establishment of RGIPT as outlined above, it is proposed that RGIPT be incorporated as an "Institute of National importance" through an Act of Parliament having a governance structure as well as legal empowerment to grant degrees in a manner similar to that enjoyed by the IITs.

The question was proposed.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं इस राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस संस्थान का जो स्थान होगा, वह उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में और भी कई पिछड़े जिले हैं, जहां पेट्रोलियम आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है, इसका चयन वहां होना चाहिए था। लेकिन यह चयन चाहे जिस कारण से भी हुआ है, जो तर्क आज दिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा की गई थी। उस तर्क के अंतर्गत यह बात कही गई है कि राय बरेली के अंतर्गत जो जायस स्थान हैं, वहां अवस्थापना सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं, जहां पेट्रोलियम की भी सुविधा प्राप्त हो सकती है, इसलिए यह संस्थान वहां होना आवश्यक है। अवस्थापना सुविधाओं में बताया गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशन्स भी हैं, चाहे एम्०बी०ए० का होगा, चाहे आई०आई०टी० का होगा, इस तरह की बात भी कही गई है। यह भी कहा गया है कि यहां से तलहटी का क्षेत्र है हिमालय है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें अनुसंधान की दृष्टि से भी काफी सुविधा प्राप्त होगी, आदि-आदि सुविधाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यह बात सही है कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी की जरूरत थी और चयन करते समय जिस प्रकार की सुविधाओं का वर्णन किया गया है, अगर इसके बारे में और भी सर्वेक्षण किया जाता, तो शायद और अच्छे स्थान मिल सकते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में ही मथुरा रिफाइनरी है। मथुरा में भी पर्याप्त जमीन है। वहा इंस्टीट्यूशन्स हैं। बगल में आगरा है, कानपुर में तो आई०आई०टी० है ही। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तलहटी की दृष्टि से देखा जाए, गंगा के किनारे की दृष्टि से देखा जाए और छोटे शहर के रूप में देखा जाए, तो बड़े शहरों का चयन इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि वहां आबादी है, भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी, अवस्थापना सुविधाओं का जैसा विस्तार होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाएगा, यह सोचकर बड़े शहरों को चयनित नहीं किया गया, अच्छा किया, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वहां और भी छोटे स्थान थे। वाराणसी के पास गाजीपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, ये सारे ऐसे स्थल हैं, जिस मापदंड को लेकर राय बरेली को चयनित किया गया है, वे सारे मापदंड इनसे फुलफिल होते हैं। यह वहां भी हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक है कि वहां ...(**व्यवधान**)...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): If you don't want it in UP, then we are interested in Karnataka. You should be grateful to the Government. At least it is in UP you must be thankful.

श्री कलराज मिश्र: मैं पुजारी जी का बहुत सम्मान करता हूं और जब पुजारी जी बोलते हैं तो मैं उनका भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूं। मैं यह आग्रह करूंगा कि पुजारी जी अपने भाषण में अपना यह दृष्टिकोण रखें तो अच्छा होगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में कई संस्थान हैं। राय बरेली अच्छा स्थान है, इसमें कोई हर्ज नहीं, अमेठी भी अच्छा

स्थान है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है उन्होंने वहां विकास की गंगा बहाई है, लेकिन अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या पर्याप्त है, काफी है। जगदीशपुर में बड़ा उद्योग है लेकिन वहां जिस तरीके से बेकार नौजवानों का समायोजन, उस इलाके के लोगों का होना चाहिए, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि नहीं हो पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कि वहां उद्योग विकसित किए गए हैं, परंतु मेरा यह कहना है जैसे वहां का ध्यान रखा गया है उसी प्रकार से और भी स्थानों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। मैंने तो केवल उस तर्क को दिया है, जो तर्क स्टैंडिंग कमेटी और मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तर्क यह दिया गया है कि जायस में यह संस्थान क्यों स्थापित होना चाहिए। उसके जो तर्क थे, वही मैंने आपके प्रस्तुत किए हैं। अगर यह मानदण्ड है तो यदि आपने और उद्योगों को चयनियत किया होता, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है, उसका किया जाता तो हर प्रकार की सुविधाएं मिलती। उधर से नेपाल भी नजदीक पड़ता है। हिमालय की तलहटी अनुसंधान के लिए पर्याप्त है। वहां पर्याप्त पानी है बड़ी गंगा, छोटी गंगा-गंडक को छोटी गंगा बोलते हैं और गंगा तो बढ़ी गंगा है। अगर उधर कच्चा तेल जाता, राय बरेली आएगा, महंगा है, पैसे ज्यादा लगेंगे, वहां भी जा सकता है अगर चयन करने में यह स्थिति रखी गई होती, तो शायद मैं मंत्री जी का और अधिक स्वागत करता। मैं स्वागत तो जरूर कर रहा हूं कि इसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगर इन इलाकों की तरफ ध्यान दिया गया होता, तो बड़ा ही स्वागतयोग्य होता और यह लगता कि सही मायने में सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रीगण का जो स्थान था, वहां विकास की प्रक्रिया तो तेज थी ही, आज भी तेज है, इन्होंने चिन्ता की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी कैसा विकास हो, प्रदेश के बाकी क्षेत्रों का कैसा विकास हो, इसकी भी पर्याप्त चिन्ता की है। दृष्टि की विशालता का, दृष्टि की व्यापकता का और उस vision का एक लाभ प्राप्त होता और लोग उसकी प्रशंसा करते। इसलिए मैंने इतना वर्णन किया है।

मान्यवर, मैं इस बात की जरूर तारीफ करूंगा कि इस प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। अभी पूरे देश भर में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 13 है। 13 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कानपुर, रूड़की खड़गपुर 7 ये है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ में है। श्री चित्र तिरूमल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम में है। राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली में है। दक्षिण भारती हिन्दी प्रचार सभा चेन्नई और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में हैं। ये 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का मतलब उसकी स्वायतता से होता हैं जब स्वायतता प्राप्त होती है, तो वे अपने अनुरूप व्यवस्था कर सकते हैं। यह बात सही है कि इस संस्थान को स्थापित करते समय जो लागत आ रही है, 432 करोड़ की लागत आ रही है, 250 करोड़ इंडस्ट्री की तरफ से है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यही बताया है। शेष व्यवस्था करेंगे। यह एक अच्छी चीज है कि निगमन का यह रूप है, कारपोरेट का यह रूप है। वे अपने तरीके से आय का स्रोत और विकसित कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता बहुत है, इसमें कोई सन्देह नहीं। दुनिया के इस प्रकार के पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी सम्बन्धित जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के अन्दर इसकी गणना होगी। जैसा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, अगर सही मायने में उसको ढंग से करने की कोशिश करेगें, इन्होंने कहा है कि 2019 तक शायद इस प्रकार के लगभग 36 हजार प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है, ऐसा कुछ आंकड़ा दिया गया है। यह एक अच्छी चीज़ है कि इस प्रकार की तैयारी हो रही है। इन्होंने इस संस्थान के लाभ के बारे में जो बताया है, इस संस्थान की आयोजना अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों सहित पेट्रोलियम उद्योग के सभी प्रभावों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई है। यह संस्थान पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और उनके बीच समन्वय बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में भी समर्थ होगा। इससे उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और आंभकरणों के साथ संयोजन को भी बढ़ावा मिलेगा। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आरपीआईपीटी को उसके शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्रियाकलापों में कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त हो। इसलिए इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में घोषित किया गया है कि इसको पूरी स्वायत्तता मिल सके। मान्यवर, जिस प्रकार की प्रशासनिक एवं संगठनात्मक व्यवस्था इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से रखी है, निजी क्षेत्र के निर्देशकों में से शायद दो को नामांकित करने की बात कही गई है। मेरा कहना यह है कि इस संबंध में जो लोग विशेष तकनीकी ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों को भी इसके अंतर्गत आमंत्रित किया जाना चाहिए। तलहटी क्षेत्र के लोग, नदी क्षेत्र के लोग और पेट्रोलियम के इलाके के लोग इसके बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों को इसमें लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिनका भूगर्भीय जानकारी हो, ऐसे लोगों को भी इसके अंतर्गत

नामांकित किया जाना चाहिए। मैंने यह बात इसलिए कही है, क्योंकि इस बात का उल्लेख इसमें नहीं है। अगर आप उनको इसमें नामांकित करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वे लोग ही कर सकते हैं।

इन्होंने एक चीज़ तो इसमें दी है कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत हम भूकंप संबंधी जानकारी कर सकेंगे, लेकिन इससे संबंधित जो जानकार हैं, एक्पर्ट हैं, उनकी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। इसमें इसका उल्लेख नहीं है। जिनकी जियोलॉजी में अच्छी जानकारी है, अगर ऐसे लोगों को भी इसमें रखा जाए, तो स्थान-स्थान पर रिसर्च करने में एवं इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करने में सुविधा प्राप्त होगी। केवल पेट्रोलियम क्षेत्र ही नहीं, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्पर्ट हैं, जो तकनीकी जानकारी के भी एक्सपर्ट हैं, तकनीकी जानकारी की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, उनको भी इसमें नामांकित किया जाए और इसका सदस्य बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि जिस महत्व का राष्ट्रीय संस्थान हम बनाने जा रहे हैं, वास्तव में वह राष्ट्रीय संस्थान उस स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। यहां एक-एक चीज का वर्णन करने की आवश्यकता मैं अनुभव नहीं करता, लेकिन सब मिला कर एक अच्छा ढांचा बनाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन जिस प्रकार के लोगों को जोड़ने की अभी हमने बात की है, अगर ऐसे लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाएगा, तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इस संस्थान का संदर्भ लेकर मैं इस सरकार से यह भी कहूंगा कि जिस ढंग से रायबरेली में यह संस्थान बनाया गया है, अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के और संस्थान बनाए जाएं। अगर फैशन टेक्नोलॉजी को लिया गया है, तो यह केवल रायबरेली में ही न रह जाए। अगर मान लीजिए कि वह क्षेत्र बनुकरों से संबंधित हो, कार्पेट से संबंधित हो, बनारसी साड़ी से संबंधित हो, तो छोटे-छोटे अन्य स्थान भी उसके लिए हैं, जैसे आज़मगढ़ है, मऊ है, मुबारकपुर है एवं वाराणसी है। वाराणसी में जरी और बनारसी साड़ी का उद्योग है, कार्पेट के लिए भदोई है, मिर्जापुर है, इन स्थानों पर फैशन टेक्नोलॉजी का काम बहुत अच्छा हो सकता है। सब मिला कर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन उधर, उन छोटे-छोटे जिलों में भी बनने चाहिए। अगर सरकार इन बातों पर भी विचार करे, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयुक्त होगा। ये सारी बातें कहते हुए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Bill, 2007, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने भी इस बात का स्वागत किया है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता भी है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम समय में देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज प्रारम्भ कर दी गई है। वैसे देश में उन भूगर्भीय पदार्थों की खोज के बारे में हम निरंतर पिछले 60 वर्षों से प्रयत्न करते रहे हैं। मुझे याद है कि पं० जवाहर लाल नेहरु ने एक बात कही थी कि अगर देश को आगे बढ़ना है, देश को दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तुलना में या उनके समकक्ष आना है, तो हमें तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होगी और बिना तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान के देश की प्रगति सम्भव नहीं होगी। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि बीते 60 वर्षों में हमने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस संस्थान की स्थापना के पीछे जो भारत सरकार की सोच रही है कि हमें इस देश में जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो तकनीकी ज्ञान को जानने वाले लोग हैं, उनकी कमी को पूरा करना है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि हमारे देश में सन् 2019 में करीब 30 हजार ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी, आखिर इनकी प्राप्ति कहां से होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के अनेक स्थानों में, देश के अनेक प्रदेशों में ऐसे तकनीकी संस्थान स्थापित हुए हैं, लेकिन उनके साथ-साथ अगर उसमें एक अतिरिक्त संस्थान की स्थापना राय बरेली के जायस में होती है, तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री कलराज मिश्र जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने कहा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इस संस्थान की स्थापना होने जा रही है। स्थान के चयन के बारे में मंत्रालय ने तथा भारत सरकार ने काफी खोज-बीन की है। उस स्थान का क्या महत्व है, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्थान नेशनल हाई वे पर है। इससे लोगों को सुविधा होगी, लोगों को सुविधा होने के साथ-साथ वहां जो अन्य संस्थान बने हुए हैं, यह उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा।

1.00 P.M.

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, स्व॰ राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था। वह सपना, उन्होंने कहा था कि भारत जब सन् 2001 में पहुंचेगा, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हिन्दुस्तान ने तकनीकी क्षेत्र में और विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन के, संचार के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। लोगों को विश्वास नहीं होता था और लोग कहा करते थे कि सन् 2001 में भारत में क्या तरक्की होने वाली है, क्या प्रगति होने वाली है, भारत कहां पहुंच जाएगा? आज हम इस बात को कह सकते हैं कि स्व॰ राजीव गांधी जी देश के एक ऐसे प्रधान मंत्री हुए, जिन्होंने इस सपने को देखा तथा सपने को साकार करने की दिशा में प्रयत्न किये। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज भारत दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है।

माननीय मंत्री जी, इस संस्थान विधेयक में जो बिल या धाराएं आपने प्रस्तुत की हैं, उन पर मैं कहता हूं कि इसमें किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस संस्थान के विजिटर्स लिस्ट में माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी उल्लेख है। देश के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, जिसका अपना एक महत्व है, पूरे देश में जिसका महत्व होगा, इसके साथ अगर उस संस्थान में माननीय राष्ट्रपति महोदय जाते हैं, तो उसका मतलब यह होगा कि दरअसल उस संस्थान की देख-रेख या संस्थान के काम करने के तौर-तरीकों में भी बहुत परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के साथ-साथ मैं इस बात को भी कहूंगा कि इसमें जो धनराशि व्यय होगी, जो खर्च होगी, वह धनराशि बहुत अधिक नहीं है। देश में तकनीकी ज्ञान को जानने वालों की आवश्यकता है। जहां सन् 2019 में 36 हजार लोगों की आवश्यकता होगी और खुशी की बात तो यह है कि इस संस्थान की शुरुआत सन् 2008-2009 से हो रही है, ताकि हम प्रशिक्षण का काम कर सकें। प्रशिक्षण के काम को करने के साथ-साथ देश के उन स्थानों में, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे पुदुचेरी जाने का भी मौका मिला और मैंने इस बात को देखा कि ऐसे संस्थान वहां कायम हैं तथा भूगर्भीय क्षेत्र के परीक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस देश के कई स्थानों में यह हो रहा है। आखिर तकनीकी ज्ञान के जानने वालों की आवश्यकता देश में हमारे अपने लोगों में से ही पूरी होने वाली है, कहीं बाहर के लोगों को बुलाने की आवश्कयता नहीं होगी। हमारे देश में इतनी क्षमता है कि हम अपने देश में इस प्रकार के नौजवानों को प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण देकर उन्हें इस लायक बनाएं कि हमें पेट्रोलियम पदार्थों में, आज हमारी...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Just a minute, Voraji. Now it is 1.00 p.m. I think, we will complete this Bill, and, then, we will have a lunch break up to 2.30 p.m. Now, no lunch break please continue Voraji, but be brief.

SHRI MOTILAL VORA: Sir, I rarely speak in the House.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आप बोलिए, बोलिए।

SHRI MOTILAL VORA: Sir, I will conclude within five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are such a senior leader, आप बोलिए।

श्री मोती लाल वोरा: Okay, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आज हम अपने पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर करते हैं और हमारे तेल की आवश्यकता की पूर्ति उन से करते हैं।

महोदय, आज हमारी तेल उत्पादन की क्षमता लगभग 30 फीसदी के आसपास है, बाकी 70 फीसदी तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। महोदय, देश में कई स्थान हैं जहां तेल की खोज हो रही है और हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर आने वाले वर्षों में इस में 70 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो फिर हम जहां आज दुनिया के दूसरे देशों पर तेल की आवश्यकता के लिए निर्भर करते हैं, उस निर्भरता की आवश्कयता ही नहीं पड़ेगी। हम अपने ही देश में अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।

महोदय, स्थान के चयन के बारे में मैं माननीय कलराज मिश्र जी से कहना चाहूंगा कि चाहे वह स्थान जायस में हो, आगरा में हो, मथुरा में हो या इलाहबाद में हो, उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई प्रदेश नहीं है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस बात का आकलन माननीय मंत्री श्री मुरली देवरा जी ने किया,

मैं उन को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उन्होंने वहां इतने बड़े संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। साथ ही भारत सरकार ने इस निर्णय के कार्यान्वयन की दिशा में जो कदम उठाए हैं, मैं उनका पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for having given me the opportunity. At the outset, I will, definitely, compliment the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas for bringing forward this Bill which envisages establishment of an Institute of national importance, for increasing the number of technologically competent people in the petroleum technology, particularly, the exploration technology in the country, of which there is a serious shortage. While complimenting this, let me also say that it is a belated step. Around 1970, the country's dependence on petroleum import was about 30 per cent. Now, I think it is 70 per cent plus. The way the demand of petroleum is increasing, *vis-a-vis* the petroleum being produced within the country, the dependence on petroleum imports is going to increase much more in the fututre. It will go beyond control. Steps to produce petroleum on a war-footing basis within the country need to be taken. It is not an impractical proposition. Many other countries which do not have petroleum reserves, that is, reserves of natutal resources, they can't dream of it; they have to depend on imports. But, geologically, it has been proved that we have much more reserves which we are yet to exploit and produce petroleum. So, in that situation, India is having a very great potential, India is having immense potential for increasing its capacity to produce fuel inside the country, to produce this vital energy within the country. But our infrastructure, our manpower is not yet ready to take up that big challenge. So, in that situation, this effort of bringing up an Institute to increase the technological manpower of the country in the concerned field is a good step. However, it is belated. But better late than never. It is welcome.

The second point that I would like to suggest is, while the Institute of Petroleum Technology will be in place, we must stress more on exploration side and also on the refining side. There should be a balanced approach on both the sides. Why I am saying this is because if we see the problem being faced even in refining. Sir, the old refineries in our country are also facing problem *vis-a-vis* the latest refineries that have been set up in our country with updated technology. The main point is to take care of the additional sulphur content in the petroleum in the process of refining and also to keep the cost of refining within limit so that we can produce the refined petroleum both imported and domestically-produced in a cost-effective manner. In these areas also, there is dearth of enough technological manpower, technical manpower in the field of chemical engineering, in the fields of geological and metallurgical engineering. So, in these areas also, we have dearth of manpower and, I think, with this general engineering degree, they ought to also specialise, focus on the refining technology area as well. We must also promote research and development in these areas. I think, the Institute should also give due importance to the R&D work in fine-tuning the refining technology which we do have. We do have indigenous technology in our command to make it fine tuned, to take care of composition of the imported crude and to refine it at the least cost, so that the petroleum can be made available to the people at a cheaper rate. So, this area is also needed to be given due importance in the Institute's curriculum, and, on that also, I give my humble suggestion to the hon. Minister.

Sir, I think there is not much to be told, but the third point that I would like to make is this. As is clear from the Bill and also from the finding of the Standing Committee, the shortage is very high. As is mentioned in the Statement of Objects and Reasons, — the hon. Minister also mentioned it while introducing the Bill — there is a shortage of 36,000 personnel. But,

Sir, the Minister should have given a break-up as to how much shortage is there in the exploration side and how much shortage is there in the refining side. So far as the exploration side is concerned, after NELP, newer fields are coming under exploration and that area also is getting more priority in the days to come. So, the break up of the shortage also needs to be looked into in deciding the number of seats in different wings, exploration technology side and also refining technology side. So, that also has to be looked into in deciding the number of seats in the concerned areas. But in spite of whatever number of seats a single Institute like this can ensure, the problem of shortage will still remain because the demand for the enough-petroleum-technology-competent people will increase. It is not only in India. As per the Report, India is supplying technologically-competent persons in this field for the entire Asia. That is a reality. Sir, we will produce students. But the moment they will get the offer of a fat salary from abroad, they will go out. So, the purpose will not be served. So, there should be creation of enough persons and, for this purpose, one Institute is not sufficient. Keeping that in view, I must compliment the hon. Minister again. The Bill contains a provision in section 10 which provides that the Institute can also establish campus and academic centres in different parts of the country. One Institute cannot meet the demand that is coming in a big way, particularly after the Sixth Round of NELP. More and more fields are being brought under exploration. At the same time, the pressure on the refining sector has also been increasing. That cannot be managed by just one Institute. So, I think, the provision is there in the law. While supporting the Bill wholeheartedly and while wishing it all the success, I also request the hon. Minister and, for the matter, the Government of India, to expedite the process simultaneously establishing campus and academic centres in different parts of the country. An Institute will be there at that particular place. At the same time, the Institute must plan and open campus and academic centres in different IITs throughout the country giving priority to the petroleum-rich areas in the country, particularly in the eastern part, in the North-East, in the southern part in the Cauvery-Godavari basin, as also in the western part of the country. Keeping that in mind, they must create campuses.

My last point is that the Institute is going to be funded from the Budget by the petroleum PSUs and from the OID funds. Its control, its leadership should also be tuned in that direction. We are setting up an Institute by spending so much money from the public exchequer. It should be for public good. So, it should be controlled by a public body, not a private body. That also must be ensured. And for that also, protection should be given.

With these suggestions, I again support the Bill and thank the hon. Minister.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय महत्व की संस्था 'राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी' की स्थापना के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, माननीय कलराज मिश्र जी ने बहुत अच्छा भाषण किया। वे अंदर से प्रसन्न भी बहुत हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के एक इंस्टिट्यूट की स्थापना हुई है, मगर चूंकि विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए स्थान की बात को लेकर [illegible] अपनी थोड़ी आपत्ति की है। लेकिन अंदर से, जैसा मैंने कहा, वे बहुत प्रसन्न हैं! ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: भंडारी जी, मैंने समर्थन किया है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं वही कह रहा हूं, एक बार अगर आप खुले हृदय से स्वागत कर देते तो और भी अच्छा होता।

महोदय, मैं बिहार से आता हूं, मगर पता नहीं मंत्री महोदय का बिहार की तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। धनबाद में पहले एक माइनिंग इंस्टिट्यूट था, लेकिन बिहार के बंटवारे के बाद वह झारखंड में चला गया। एक तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, मगर उसकी क्षमता बहुत कम है, उसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। मिश्र जी के राज्य में, कानपुर में

एक IIT है। मथुरा रिफाइनरी की भी वे चर्चा कर रहे थे, बिहार का बंटवारा हो जाने के बाद मिनरल्स तो बिहार से चले ही गए, जो अच्छे इंस्टिट्यूट थे, वे भी झारखंड के पास चले गए। मैं तो मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी प्रकार एक बार बिहार पर भी उनकी दृष्टि जानी चाहिए। ...(व्यवधान)...

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): किया है, रायबरेली के लिए किया है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: उसके लिए तो मैंने बधाई दी है, धन्यवाद किया है।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: दोबारा धन्यवाद दीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: गुप्ता जी कह रहे हैं कि रायबरेली के लिए आपने किया है, उसके लिए हमारी पार्टी की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि पैट्रोलियम के लिए हमें विदेशों पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। इस बारे में मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उस कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हूं। हमें चिंता रहती है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो आवश्यकता है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। अभी तक 30 परसेंट ही sedimentary basin की खोज कर सके हैं, हमें और खोज करनी है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बिल में कहा है कि 2019 तक 36,000 जो trained personnel हैं, उनकी कमी हो जाएगी, हमें उस कमी को पूरा करना है। यह राष्ट्रीय महत्व का इंस्टिट्यूट है, तो इसके लिए धन की जो भी आवश्यकता होगी, scientists की जो भी आवश्यकता होगी, technical experts की जो भी आवश्यकता होगी, उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि वे बिहार में भी इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Ekanath K. Thakur; not more than three minutes.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Sir, I am very happy that this Bill has been introduced and I support this move. Uttar Pradesh has a population more than that of Pakistan and, therefore, if the Government sets up an institute of national importance there, there is nothing to grudge about by anyone. But, while setting up institutes in future, areas like Assam and areas like Maharashtra where Bombay High was first discovered, should also be kept in view. This Institute will train professionals who will be experts in the entire hydro-carbon chain, that is, upstream, midstream and downstream. And, the Institute will look after the requirements of education, research, engineering and technology. India has always boasted of having the third largest engineering mind power and in the areas of petroleum and hydro-carbon. With this Institute of national importance, we may also be able to get the expertise that is need by us to explore our hydro-carbon resources. With the publication of the book, *"Limits to Growth"* in 1970s by the Club of Rome, it was pointed out as many as about 34 years ago that hydro-carbon resources are exhaustible. I think, while we undertake the search with satellites and earth observation satellites and other means of our hydro-carbon resources, as major nation which houses one-sixth of the total population of this planet, we should be in a position to know what is our total hydro-carbon wealth and if that prediction of Club of Rome is to come true that all our hydro-carbon resources are going to be exhausted over the next century, then we should know which are the areas which we are to conserve for future. For example, the United States of America have very large resources in Alaska. But, they have a policy decision not to exploit their resources till they first use and exploit all the oil and petroleum in the Arab lands and Soviet Russia. Sir, we should have a policy about hydrocarbons as to which are the areas we are going to explore, which we are going to reserve for our progeny and posterity. Sir, I think, this research, which is going to be undertaken by this institute, will include these areas also so that we have

certain strategic results. For example, if you see minerals, so far as iron ore is concerned, right now, it is being exported, in a big way, to China for the 2008 Olympics and to other parts of the world without having a holistic view as to what would be our requirement for infrastructure in the days to come. The Government has still not come up with a policy about many minerals. I am citing just one example. I think, we have a myopic policy, a very short-sighted policy, where our iron-ore is being exported in large quantitites abroad, which, in a way, is threatening the future of infrastructure in our own country. While making these preliminary remarks, I want to invite the attention of the hon. Minister, Shri Murli Deora, who is a great friend of our Party also, towards Section 11, which says, "The institute shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and, no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting or appointing students, teachers or employees or in any other connection whatsoever. (*Time-bell*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude your speech.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, am I expected to understand from this clause that the reservation policy would not be applicable to this institution because Section 11 says that there shall be no discrimination whatsoever against any student, any teacher or any employee, and, if the Government has gone this further and it wants to do everything on merit, I would like to take the opportunity to congratulate the hon. Minister and the Government for saying that there will be no discrimination on the ground of sex, race, caste, creed or religion.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I have one very important suggestion to make. Under clause 13, it has been mentioned that the President of India shall be the Visitor of the institute. In case of Central Universities, the President of India is the Chancellor, and, in case of State Universities, the Governor is the Chancellor, and, then, the Chancellor's powers are defined. In clause 13, a small statement has to be made about the Visitor's powers. Moreover, Sir, the 'Visitor' has not been defined. Under clause 3 of the Act, every other authority has been defined but the term 'visitor' has not been defined. Therefore, the role and authority of the visitor should be defined.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude now.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I am concluding. I have one more thing to mention. As far as the research work is concerned, there are so many basins, for example, Godavari basin and others, where the ONGC has partnership with the private sector. There are numerous complaints that the private sector, which has twenty or thirty per cent partnership, are bribing the officials of ONGC and other authorities, and, taking away a large part of hydrocarbons taken out from these areas thereby enriching themselves. So, the research should go in a direction that whenever we exploit resources from the ground or the sea, there should be a way of calculating before it is transported from that place and that should be an automatic system so that the country is not deprived of the revenues. Some industrialists are enriching themselves by causing ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have already made that point. Please conclude. *(Interruptions)*

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, they have a small partnership with ONGC and they scoop out a large amount of petroleum and that happens to be the only source of the growth of their industry or group. *(Time-bell)* This has to be borne in mind. I thank you for having given me the opportunity to make my points.

श्री मुरली देवरा: सर, मैं सम्माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल पर चर्चा में भाग लिया। शुरुआत में कलराज मिश्र जी ने जो सुझाव दिया, यह सही है कि कोई भी संस्था कहीं न कहीं तो स्थापित करनी पड़ेगी, तो जायस भी ऐसी ही जगह है। मिश्र जी, कभी हम आपको वहां ले जाएंगे, नहीं तो ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि वहां बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत अच्छी संस्था वहां बनेगी। ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: मैं जायस बहुत बार गया हूं, वहां काफी घूमा हूं।

श्री मुरली देवरा: वहां जब इंस्टीट्यूट आएगा, तब की बात मैं कह रहा हूं। सर, 130 मिलियन टन ऑयल हम भारतवर्ष में consume करते हैं और 110-112 मिलियन टन इम्पोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि 35-36 डॉलर, 40 डॉलर के करीब का भाव था और आज 96 डॉलर, 100 डॉलर का भाव है। फिर भी आपने देखा होगा कि चार पदार्थ, जो कि हमारी मिनिस्ट्री handle करती है — पेट्रोल, डीज़ल, एल॰पी॰जी॰ और केरोसिन, एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया है। 9 रुपए प्रति लीटर केरोसिन दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। क्यों लालू जी, ठीक है?

श्री लालू प्रसाद (बिहार): ठीक बात बोली है आपने!

श्री मुरली देवरा: हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब लोगों का ईंधन है, उसका भाव नहीं बढ़े, हालांकि सरकार को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, यह आपको मालूम है। ऐसा ही मेरे दोस्त ने रिफाइनरी के बारे में कहा। अभी आपको मालूम है तीन रिफाइनरीज़ Paradip (उड़ीसा) में, भटिंडा (पंजाब) में और बीना (मध्य प्रदेश) में आ रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): केंद्र सरकार तो बेचती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें 22 रुपए तक में बेच रही हैं, जैसे बिहार में।

श्री मुरली देवरा: लालू जी जब फिर से मुख्य मंत्री बनेंगे, तो ठीक हो जाएगा। कोई ज़माना था कि ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): इनको निकालना चाहते हैं क्या?

श्री लालू प्रसाद: आप तो मेरे मित्र हैं, आज चुपचाप बैठे हुए हैं?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: आज शुक्ल जी को बगल में बैठा लिया? ...(व्यवधान)...

श्री मुरली देवरा: महोदय, कोई ज़माना था कि gems & jewellery का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारतवर्ष में होता था। आज भारतवर्ष से सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने की चीज, 18.6 बिलियन डॉलर की, ऑयल और इसके प्रोडक्ट्स हैं। खासकर, रिफाइनरी की बात मैं आपको बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में — प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस और एस्सार और पब्लिक सेक्टर में हमारी जो रिफाइनरी है, वह बहुत अच्छा काम कर रही है। जब Chevron, Exxon Mobil, इन कंपनियों के चेयरमैन भारतवर्ष में आते हैं, वे कहते हैं कि हमारी रिफाइनरीज़ — पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज्यादा अच्छी चल रही हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको हम अमल में लाएंगे। एक चीज़ फिर मैं कह दूं, भंडारी जी ने जो बिहार के बारे में कहा, जब हम एन॰ई॰एल॰पी॰ के अंदर नीलाम करते हैं, ऑक्शन करते हैं, बेचते हैं ब्लॉक को, उसमें कोल बैड मीथेन अभी शुरू हो रहा है और आसनसोल वगैरह में ऐसे-ऐसे कोल बैड मीथेन अभी निकले हैं, इतनी गैस निकली है कि आप सोच नहीं सकते। कृष्णा-गोदावरी (आंध्र प्रदेश) के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैस निकली है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में शायद हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़े। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री वी॰ नारायणसामी (पुडुचेरी): सर, कावेरी बेसिन के बारे में भी बात कीजिए। कावेरी बेसिन में ...(व्यवधान)...

श्री मुरली देवरा: मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आप इसको पूरा सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith, be taken into consideration".

The motion was adopted.

CLAUSE 2

Declaration of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology as an Institution of National Importance

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In Clause 2, there is one amendment (No.1) by the hon. Minister.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

1. That at page 2, line 2, *for* the word "Jias" the word "Jais" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.

CLAUSE 3

Definitions

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In Clause, 3, there is one amendment (No.2) by the hon. Minister.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

2. That at page 2, line 22, *for* the world "Jias" the word "Jais" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clauses 4 to 14 were added to the Bill.

CLAUSE 15

Establishment of General Council

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In Clause 15, there are four amendments (Nos. 3-6) by the hon. Minister.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

3. That at page 6, line 39, *for* the words "the Chairman and Managing Director, Indian Oil Corporation" the words "the Chairman, Indian Oil Corproation Limited" be *substituted.*

4. That at page 7, line 5, *for* the words and bracket "the Advisor (Energy)" the words and bracket "the Principal Advisor (Energy)" be *substituted.*

5. That at page 7, line 8, *for* the words "the Dean, School of Chemical Technology" the words "the Director, University Institute of Chemcial Technology" be *substituted.*

6. That at page 7, line 9, *for* the words "Oil India Development Board" the words "Oil Industry Development Board" be *substituted.*

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clauses 16 to 40 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The House stands adjourned to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House met at thirty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' BILLS

The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2007

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MAHENDRA MOHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Prohibition on Use of Coercive Methods for Recovery of Bank Loans Bill, 2007

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the use of coercive methods such as, intimidation and harassment either verbal or physcial against any person or his family for recovery of loan, by Banks or their agents whether authorized or not and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MAHENDRA MOHAN: Sir, I introduce the Bill.

The Coaching Centres (Regulation And Control) Bill, 2007

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation and control of coaching centres providing coaching for various kind of entrance examinations for higher educational and professional course including medical and engineering education and for jobs in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.